(ग) भविष्य में वहां पर भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)) : (क) एक व्यक्ति मारा गया था । तीन घायल हो गए थे लेकिन अब ठीक हैं ।

(ख) हविलदार मंगल चन्द के परिवार को, जिनकी मृत्यु नवम्बर 1967 में हनोई म हो गई थी, 35,000 रु० दिए गए हैं जो कि अमरीका सरकार ने मुआवजे के रूप म हमें भेजे थे । इसके अतिरिक्त कमीशन की बीमा योजना के अन्तर्गत भी उनके परिवार को कुछ रक़म दी जाएगी ।

(ग) कमीशन के अध्यक्ष को सलाह दी गई है कि अगर स्थानीय अधिकारी हमारे दलों की, जहां वे हैं, वहां अथवा उसके आस-पास कहीं हिफाजत करने का आश्वासन न दें तो वे अपने दलों को सैगोन ले जाएं ।

DEFENCE OF ANDAMAN ISLANDS

*605. SHRI D. N. PATODIA :
SHRI YASHPAL SINGH :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the Prime Minister's recent visit to Andamans, the local population had represented to her that 260 Islands strategically situated in the Bay of Bengal were not being protected adequately; and

(b) if so, whether adequate steps have been taken in this matter ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) No, Sir.

(b) Appropriate steps have been taken for the security of the Andaman & Nicobar Islands. These steps are being reviewed from time to time by the Government.

अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण

*606. **श्री ओ० प्र० त्यागी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा के बढ़ते हुए व्यय और चीन तथा पाकिस्तान के निरन्तर खतरे को देखते हुए क्या सरकार का विचार देश के सभी स्वस्थ युवकों तथा युवतियों को अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण देने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) सर्वसाधारण जनता को सैनिक प्रशिक्षण अथवा हथियारों का इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने के लिए पहले से ही कई किस्म की योजनाएं प्राप्य हैं । इनमें शामिल है :—

(1) छात्रों के लिए एन० सी० सी०

(2) प्रादेशिक सेना ।

(3) गृह मंत्रालय की असैनिकों के लिए राईफल प्रशिक्षण योजना; और

(4) होम गार्ड ।

किसी आपात स्थिति में रक्षा की आवश्यकताओं के लिए इन द्वारा पर्याप्त मूल आधार प्राप्य है । देश की जन संख्या के अधिकतर और चुनाव में अन्तर्ग्रस्त भेदभाव के कारण, अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की किसी भी योजना को, प्रशिक्षण के लिए रक्षा सेविवर्ग और साज-सामान तथा खर्च जुटाने सम्बन्धी कई कठिनाइयों का सामना करना होगा; इस बात में भी सन्देह है कि ऐसी किसी योजना की वास्तव में आवश्यकता है भी । इन परिस्थितियों में व्यावहारिक बुद्धिमता यह होगी कि जैसा ऊपर बताया गया है सीमित आधार पर आगे बढ़ा जाए ।